

समक्ष एम.एम कुमार और गुरदेव सिंह, माननीय न्यायमूर्ति।

वन्दना और अन्य, -याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य -प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी संख्या 2895 - 2010 की कैट

30 अगस्त 2011

भारत का संविधान अनुच्छेद 14, 16(1) और 226 - कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) - केंद्र (प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ताओं की नियमितीकरण की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्हें एसएससी प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती नहीं किया गया था, लेकिन यह देखते हुए कि आवेदकों की सेवाओं का उपयोग किया गया है) 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए और प्रतिवादी विभाग ने कभी भी एसएससी की प्रक्रिया के माध्यम से नियमित चयन नहीं किया है - इस प्रकार उत्तरदाताओं को एक प्रक्रिया विकसित करने के लिए कदम उठाने चाहिए और आवेदकों को किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए नियमित आधार पर नियुक्ति - उत्तरदाता भी विचार कर सकते हैं जो रिक्तियां मौजूद नहीं हैं उनके लिए पदों का सृजन करना और आवेदकों को नियुक्त करना एसएससी के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से और आवेदकों को इसमें भाग लेने की अनुमति दी जाए और यदि वे योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें आयु में छूट के साथ नियमित नियुक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है - रिट याचिका पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर खारिज कर दी गई थी - समीक्षा याचिका दायर - आदेश वापस लिया गया - याचिका निस्तारित।

अभिनिर्धारित कि थाई संविधान पीठ ने आरएन नंजुंदप्पा बनाम टी थिमैया पर भरोसा करते हुए "अवैधता" और "अनियमितता" के बीच अंतर किया। (1972) 1 एससीसी 409 और देखा गया कि यदि नियुक्ति स्वयं नियमों का उल्लंघन है या संविधान का उल्लंघन है, तो ऐसी अवैधता को नियमित नहीं किया जा सकता है। बीएन नागराजन बनाम कर्नाटक राज्य का भी संदर्भ दिया गया। (1979) 4 एससीसी 507। संविधान के नियमों और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करके सेवा में प्रवेश करने वालों के बीच एक स्पष्ट अंतर है, जो एक वर्ग से अलग हैं, उनकी नियुक्ति अनियमित हो गई है।

(पैरा 5)

इसके अलावा, यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं का मामला उमा डीसीविस के मामले के पैरा 53 में दिए गए अपवाद के अंतर्गत आएगा क्योंकि वे थे

शुरुआत में 89 दिनों की अवधि के लिए पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था और उनके नाम रोजगार कार्यालय के माध्यम से मांगे गए थे और वे 10 वर्षों से अधिक समय तक प्रतिवादी विभाग में बने रहे थे।

(पैरा 6)

आगे कहा गया, उस याचिका का निपटारा प्रतिवादियों को उमा के अनुसार नियमितीकरण के लिए एक योजना तैयार करने के निर्देश के साथ किया गया।

डेविस की सहजता और यदि याचिकाकर्ता उपयुक्त पाए जाते हैं तो उनकी सेवाओं को तीन महीने की अवधि के भीतर नियमित किया जाना चाहिए।

(पैरा 7)

एच.सी. याचिकाकर्ताओं के लिए वकील अरोड़ा।

प्रतिवादी-भारत संघ की ओर से अधिवक्ता अश्विनी के. बंसल।

निर्णय

एम.एम कुमार, माननीय न्यायमूर्ति।

(1) अनुच्छेद के तहत दायर तत्काल याचिका में उठाया गया संक्षिप्त मुद्दा

संविधान के अनुच्छेद 226 में कहा गया है कि क्या याचिकाकर्ताओं की सेवाएं, जिन्हें शुरू में जून 1993 से अक्टूबर 1995 के बीच 89 दिनों के लिए अस्थायी आधार पर स्टेनोग्राफर (ओजी) के रूप में नियुक्त किया गया था, को नियमित किया जा सकता है और प्रतिवादियों को एक निर्देश जारी किया जा सकता है। नियमितीकरण हेतु योजना.

(2) आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 2.9.2005 के आदेश को चुनौती दी है (पी-1) केंद्रीय प्रशासनिक की चंडीगढ़ बेंच द्वारा प्रस्तुत ट्रिब्यूनल (संक्षिप्तता के लिए, 'ट्रिब्यूनल') - ट्रिब्यूनल ने आवेदक-याचिकाकर्ताओं की उनकी सेवाओं को नियमित करने की प्रार्थना को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि उन्हें कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की प्रक्रिया के माध्यम से नियमों के अनुसार कभी भी भर्ती नहीं किया गया था।), जिसे अब भर्ती का एक तरीका माना जाता है। हालाँकि, साथ ही, ट्रिब्यूनल ने पैरा 7 में निम्नानुसार अवलोकन करके मूल आवेदन का निपटारा कर दिया है:

“7. कानून के उपरोक्त प्रस्ताव के तहत जांच करने पर, हमने पाया कि आवेदकों को एसएससी की प्रक्रिया के माध्यम से नियमों के अनुसार कभी भी भर्ती

नहीं किया गया था, जिसे अब भर्ती का एक तरीका माना जाता है। इन परिस्थितियों में, आवेदकों की छूट प्रदान करके उन्हें नियमित करने का आदेश देने की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाना चाहिए। हालाँकि, हम जीवन के व्यावहारिक पक्ष से अपनी आँखें बंद नहीं कर सकते हैं जो इंगित करता है कि आवेदकों जैसे व्यक्तियों से सेवाएँ प्राप्त करके मानव संसाधनों का उपयोग किया गया है, जो व्यवस्था 10 वर्षों से अधिक की अवधि तक जारी रही है। इसका आईडी द्वारा बहुत जोरदार विरोध किया गया है। आवेदकों के वकील ने कहा कि प्रतिवादी विभाग ने एसएससी की प्रक्रिया के माध्यम से आशुलिपिक के पदों पर नियुक्ति के लिए कभी भी नियमित चयन नहीं किया है। उनका तर्क है कि कानून द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती कराने में उत्तरदाताओं की विफलता के कारण आवेदकों को इस सुविधा में नियमित नियुक्ति से वंचित किया जा रहा है। यह विवाद न केवल इस अदालत के लिए बल्कि उत्तरदाताओं के अधीन सक्षम प्राधिकारी के लिए भी विचार योग्य है। उत्तरदाताओं को कुछ ऐसी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जिसके माध्यम से आवेदक भी एसएससी के माध्यम से चयन की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त कर सकें। इसलिए, हम चाहते हैं कि उत्तरदाताओं को इस आशय के कदम उठाने चाहिए और आवेदकों को नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के लिए किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। उत्तरदाता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ रिक्तियाँ मौजूद नहीं हैं, कुछ पदों के सृजन पर भी विचार कर सकते हैं कि प्रतिवादी विभाग को बहुत लंबे समय से आशुलिपिक के रूप में काम कर रहे समान पद वाले व्यक्तियों पर इन आवेदकों की सेवाओं की आवश्यकता थी और कोई भी पद सृजित करने का निर्णय ले सकता है। आगे की पोस्ट. जब भी उत्तरदाता आवेदकों को चयन की नियमित प्रक्रिया से गुजरेंगे, एसएससी या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से कुछ प्रतिस्पर्धी परीक्षा आयोजित की जाएगी और आवेदकों को अन्य उम्मीदवारों के साथ उसमें भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। यदि वे उक्त प्रतियोगी परीक्षा में योग्य पाए जाते हैं, तो उन्हें आयु में छूट के साथ उनकी नियमित नियुक्तियों पर विचार किया जा सकता है। इस अवधि में वे पहले ही उत्तरदाताओं के अधीन काम कर चुके हैं।

(3) यह उल्लेख करना उचित है कि एक चरण में तत्काल याचिकासचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य सचिव, अन्य बनाम उमा देवी और अन्य (1) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में डिवीजन बेंच द्वारा आदेश दिनांक के तहत खारिज कर दिया गया था। 18.5.2006. इसके बाद, आवेदक-याचिकाकर्ताओं ने 2006 की समीक्षा आवेदन संख्या 207 दायर की, जिसमें कहा गया कि वे रोजगार कार्यालय के माध्यम से आए हैं और दस साल की अवधि के लिए काम कर रहे हैं, खंडपीठ ने अपने आधिपत्य द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18.5.2006 के आदेश को वापस ले लिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उमा देवी (सुप्रा) के मामले के फैसले के पैरा 53 में 4. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से

सुना है और उनकी सक्षम सहायता से पेपर बुक का अध्ययन किया है, उमा देवी (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण को अस्वीकार कर दिया है, जिन्होंने सेवा में प्रवेश किया है। अवैध आचरण.

5. संविधान पीठ ने अवैधता और अनियमितता के बीच अंतर किया है। उपरोक्त अंतर को खत्म करने के लिए उनके आधिपत्य ने आर.एन. नंजुदप्पा बनाम थिमैया के मामले में उठाए गए तर्कों का संदर्भ दिया।

(2), जिसमें यह देखा गया कि यदि की गई नियुक्ति स्वयं नियमों का उल्लंघन है या यदि यह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है, तो ऐसी अवैधता को नियमित नहीं किया जा सकता है। आगे यह देखा गया है कि किसी अधिनियम का अनुसमर्थन और नियमितीकरण संभव है जो प्राधिकरण की शक्ति और प्रांत के भीतर हो सकता है लेकिन प्रक्रिया या तरीके का कुछ गैर-अनुपालन हुआ है जो नियुक्ति की जड़ तक नहीं जाता है और वह नियमितीकरण भर्ती का एक तरीका नहीं हो सकता। यदि इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो नियमों की अवहेलना करते हुए नियुक्ति का नया प्रमुख पेश किया जाएगा, जिसका प्रभाव नियमों को अमान्य करने जैसा होगा। संविधान पीठ ने बी.एन. के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले का भी संदर्भ दिया है। नागराजन बनाम कर्नाटक राज्य (3) इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 14 और 16(1) द्वारा परिकल्पित नियमों और संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन करके सेवा में प्रवेश करने वालों के बीच एक स्पष्ट अंतर उन लोगों से अलग है जिनकी नियुक्तियाँ अनियमित हो गई हैं। यह इन परिस्थितियों में है कि उमादेवी के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने पैरा 53 में निम्नानुसार देखा है: -

53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसा मामला हो सकता है जहां अनियमित नियुक्तियां (अवैध नियुक्तियां नहीं) जैसा कि एस.वी. नारायणप्पा, आर.एन. नंजुदप्पा और बी.एन. नागराजन में बताया गया है और ऊपर पैरा 15 में उल्लिखित है, विधिवत स्वीकृत रिक्त पद पर विधिवत योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई होगी। बनाया गया है और कर्मचारी 10 साल या उससे अधिक समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के सवाल पर तय सिद्धांतों के आलोक में योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने ऊपर उल्लिखित मामलों में और में इस फैसले का प्रकाश. उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनकी संस्थाओं को एक बार के उपाय के रूप में अनियमित रूप से नियुक्त ऐसे लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाना चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन कवर के तहत नहीं अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के अनुसार और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियां की जाएं, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कार्यरत हैं। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि नियमितीकरण, यदि कोई पहले से ही किया गया है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, को इस फैसले के आधार पर फिर से खोलने की

आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को और अधिक दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित करना या स्थायी करना चाहिए।

(6) जब उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि आवेदक-याचिकाकर्ताओं का मामला उमा देवी के मामले (सुप्रा) में निर्णय के पैरा 53 में दिए गए अपवाद में आएगा। इतना ही नहीं, शुरुआत में उन्हें जून 1993 से अक्टूबर 1995 के बीच 89 दिनों की अवधि के लिए 1200 + अन्य भत्ते के मूल वेतन पर पूरी तरह से अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उनके नाम उत्तरदाताओं द्वारा विधिवत मांगे गए थे। रोजगार कार्यालय के माध्यम से और वे दस वर्षों से अधिक समय से प्रतिवादी विभाग में बने हुए हैं।

(7) उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, माननीय सर्वोच्च के निर्णय के अनुसार नियमितीकरण की एक योजना तैयार करने के लिए उत्तरदाताओं को एक निर्देश के साथ तत्काल याचिका का निपटारा किया जाता है।

कोर्ट ने उमा देवी (सुप्रा) के मामले में प्रतिपादित किया और यदि याचिकाकर्ताओं को सभी प्रकार से उपयुक्त पाया जाता है तो उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना चाहिए। इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आयुष गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पलवल, हरियाणा